standards and norms, staffing patterns etc. Any resultant economy arising out of individual studies, is to be effected by the concerned Ministries/Departments. No central monitoring is done in this regard by the Ministry of Finance.

(d) to (f). Keeping the Government expenditure under control is a continuous exercise. Instructions are issued in this regard from time to time. These instructions include reduction in posts, in expenditure on petrol/diesel, telephones etc.

Cut in military expenditure

3321. SHRI T. VENKATRAM REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the World Bank has asked both India and Pakistan to cut military expenditure;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the response of Indian Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY) :

(a) No, Sir.

(b)and (c). Do not arise

जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश की विभिन्न योजनाओं हेतु ऋण दिया जाना

3322. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कई जिलों की जलपूर्ति और मल-निकासी की योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण की राशि इस संबंध में विद्यमान मानदण्डों के अनुसार ऐसी योजनाओं की स्वीकृत कुल लागत के 50 प्रतिशत से भी कम है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा योजनाओं की लागत में वृद्धि होने पर कोई ऋण नहीं दिया जाता ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 20,000 व्यक्तियों से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में पेय जल और निकासी की योजनाओं की स्वीकृत लागत का 70 प्रतिशत भाग समान रूप से ऋण के रूप में दिया जाएगा तथा क्या निगम द्वारा इन योजनाओं की संशोधित लागत के लिए और ऋण स्वीकृत किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) . (क) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचना दी है कि वे योजना आयोग द्वारा किए गए आवंटन के आधार पर जलपूर्ति और मलव्ययन बोर्डों नगर पालिकाओं/राज्य सरकारों जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, को जल आपूर्ति और मलव्ययन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष ऋण प्रदान करते हैं। जल आपूर्ति और मलव्ययन योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का वर्तमान ढांचा इस प्रकार है :—

वित्त पोषण का ढांचा

योजना की लागत	वर्तमान ढांचा	
	शहरी	ग्रामीण
(1)	(2)	(3)
जहां लागत 1,00 करोड़ रुपये से अधिक न हो।	लागत का 2/3 भाग	लागत का 50 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)
जहां लागत 1.00 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 5.00 करोड़ रुपय से कम है ।	जहां लागत 1 करोड़ रु. से अधिक हो तो वहां 0.67 करोड़ रुपये जमा लागत का 50 प्रतिशत ।	लागत 1 करोड़ रु. से अधिक होने पर 0.50 करोड़ रुपये जमा लागत का 50 प्रतिशत ।
जहां लागत 5.00 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम है ।	लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक होने पर 2.67 करोड़ रुपये जमा लागत का 40 प्रतिशत ।	लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक होने पर 2.50 करोड़ रुपय जमा लागत का 40 प्रतिशत ।
जहां लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक हो ।	लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक होने पर 4.67 करोड़ रुपय जमा लागत का 25 प्रतिशत ।	लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक होने पर 4.5 करोड़ रुपय जमा लागत का 25 प्रतिशत ।

जीवन बीमा निगम ने सूचना दी है कि उनके विचार में वित्तीय सहायता केवल एक बार किसी भी चालू योजना के लिए संशोधित अनुमानित लागत और वास्तविक अनुमानित लागत के अंतर का 25 प्रतिशत तक बढ़ सकती है । बशर्ते कि संशोधित अनुमानित लागत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और योजना की शेष लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक निधि प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वचनबद्धता दी जाए। जीवन बीमा निगम ने सूचना दी है कि वित्त पोषण का यह ढांचा स्थानीय निकायों के लिए बहुत सी छोटी योजनाओं को निधि प्रदान करने हेतु निर्धारित किया गया है। 20,000 से अधिक की जनसंख्या वाले शहर वित्तीय सहायता के शहरी ढांचे के अन्तर्गत लिए जाएंगे । वर्तमान में जीवन बीमा निगम के पास अलग से ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं जिसमें इस प्रकार के शहरों में पेय जल/मलजल निकास के लिए स्वीकृत लागत का 70 प्रतिशत तक ऋण प्रदान किया जाए ।

Predictions about U.S. Investments in India

3323. SHRI HIPHEI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to certain predictions made by the Governor of the US State of Massachusetts and leader of the 44 member trade mission during his visit to India in recent past;

(b) whether this mission also gave the possibilities that U.S. investment destination now is India than China;

(c) if so, the details therof;

(d) whether Government propose to take some unitiatives in this regard; and

(e) if so, the details thereof and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN HE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (c) Governor William F. Weld of the State of Massachusetts; USA, had led delegation to India representing 25 US companies, mainly in the telecommunication, power, environment and engineering sectors, during February, 1995, following the Presidential Business Development Mission led by US Commerce Secretary Mr. Ronald H. Brown to India from 14—21 January, 1995. The delegation noted that the economic reforms underway in India had evoked great interest among US investors. India has been identified by the US Department of Commerce as one of the top ten emreging markets. The US Trade Mission expressed confidence and optimism about flows of US capital to India.